बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 127

नीतिगत अनिश्चितता

वृहद आर्थिक स्थिरता और नीतिगत निश्चितता निवेश के अहम कारक हैं क्योंकि कारोबारी ऐसे माहौल में निवेश नहीं करना चाहते हैं जहां आर्थिक और नीतिगत अस्थिरता हो। बीते कुछ वर्षों के दौरान भारत ने अनिश्चितता कम करने में कामयाबी हासिल की है लेकिन कुछ निर्णय, विशेष तौर पर हालिया बजट के कुछ निर्णय इस लाभ को कम कर सकते हैं। वृहद स्तर पर देखें तो लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य ढांचे ने मुद्रास्फीति संबंधी अनुमानों के मामले में मदद की है। यह बात महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इससे न केवल वृहद आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने में मदद मिलेगी बल्कि कारोबारी जगत को दीर्घावधि के अनुमान लगाने में भी आसानी होगी। अन्य चीजों के अलावा यह आशा की जा सकती है कि मूल्य स्थिरता से पूंजी की लागत कम होगी। इसी प्रकार वस्तु एवं सेवा कर ने अप्रत्यक्ष कर ढांचे की जटिलता को कम किया है, हालांकि क्रियान्वयन के कुछ मुद्दे अभी भी हल किए जाने हैं।

इसके अतिरिक्त ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता भी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के निपटान में मदद कर रही है। इससे देश की अर्थव्यवस्था की ऋण संस्कृति में सुधार होगा। हालांकि इनमें से कुछ सुधार हाल के वर्षों में लागू किए गए हैं और अभी इन पर काम चल रहा है परंतु इनका महत्त्वपूर्ण ढंग से सकारात्मक प्रभाव हुआ है। आगे चलकर इससे कारोबारी माहौल में और सुधार होगा। खेद की बात है कि सरकार के कुछ अन्य निर्णय अनिश्चितता बढ़ाने वाले साबित हुए। बजट की बात करें तो उससे एक दिन पहले पेश की गई आर्थिक समीक्षा में नीतिगत निश्चितता की जरूरत को रेखांकित किया गया था। उसमें कहा गया था कि खराब ढंग से तैयार कानून जो अस्पष्टता, संशोधनों, स्पष्टीकरण और रियायतों से भरा हो, उससे उपजी अनिश्चितता निवेशकों को निराश करती है और देश में निवेश का माहौल खराब होता है। परंतु बजट में कई स्तरों पर जटिलता और अनिश्चितता बढ़ाई गई। निवेशकों को कर दर में स्थिरता और अनुमन्यता की आवश्यकता होती है लेकिन अत्यधिक अमीर वर्ग के लिए अचानक आयकर अधिभार बढ़ाकर बजट ने न केवल कर ढांचे को जटिल बनाया बल्कि उन विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को भी प्रभावित किया जो गैर कॉर्पोरेट संस्थानों में निवेश करते हैं। पहले कहा गया कि सरकार इस विषय पर स्पष्टीकरण जारी करेगी लेकिन बाद में कहा गया कि इसकी जरूरत नहीं। कर पश्चात प्रतिफल पर दृष्टि डालने पर कुछ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक देश से बाहर जाने पर विचार कर सकते हैं। यह बात सरकार को भी प्रभावित कर सकती है जो विनिवेश का बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है। सरकार ने कई वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि घरेलू उद्योग को बचाया जा सके। यह उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करेगा और वैश्विक मूल्य शृंखला का हिस्सा बनने की हमारी कोशिश को भी। इसका असर देश की निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं पर पड़ेगा।

अगर दरें बार-बार बदली गईं तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ काम करने या यहां निवेश की अनिच्छुक हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर इसका एक और उदाहरण है। बजट में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को कर राहत दी गई। वायु प्रदूषण चिंताजनक है लेकिन सरकार के ऐसे कदम से वाहन क्षेत्र का शेष हिस्सा अनिश्चितता और जोखिम महसूस करेगा। सरकार को नियम बनाने के बाद शेष काम बाजार पर छोड़ देना चाहिए। कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं। सरकार पहले दिन से दावा कर रही है कि कारोबारी सुगमता बढ़ाना उसकी प्राथमिकता है। परंतु बजट प्रस्तावों में सीमा शुल्क अधिकारियों को राजस्व हित में या तस्करी रोकने के लिए किसी व्यक्ति को पकड़ने का अधिकार दिया गया है जिसका दुरुपयोग संभव है। ऐसे उपायों से अनिश्चितता बढ़ेगी। सरकार को राजस्व जैसे अल्पकालिक लक्ष्यों की खातिर लिए गए अपने निर्णयों के दूरगामी असर पर विचार करना चाहिए।

अजय मोहंती

देश की प्रतिरक्षा बतर्ज मेरा जूता है जापानी!

पेंशन को अलग कर दिया जाए तो 20 वर्षों में तीन प्रधानमंत्रियों के अधीन देश का रक्षा बजट जीडीपी के 1.5 फीसदी से ऊपर नहीं निकल पाया।

राष्ट्र की बात

शेखर गुप्ता

तीन बातों ने इस सप्ताह की विचार प्रक्रिया को प्रभावित किया है:

■ सामरिक समुदाय रक्षा बजट में इजाफा न होने के कारण व्यापक तौर पर हताश है।

■ द प्रिंट के सृजन शुक्ल को दिए साक्षात्कार में अमेरिकी सामरिक विद्वान क्रिस्टाइन फेयर ने कहा कि लश्कर-ए-तैयबा केवल एक और आतंकी संगठन नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना का एक कम खर्च वाला दस्ता है। इसका लक्ष्य ऐसी असंगत लड़ाई छेड़ना है जिसका मुकाबला भारत नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अल्पकालिक लड़ाई में पाकिस्तान को नहीं हरा सकता।

■ वायुसेना के दिवंगत कमांडर जसजीत सिंह ने अपनी किताब में कुछ दिलचस्प बातें लिखी हैं। मसलन कैसे भारतीय वायुसेना ने इजरायली इंजीनियरों को अपने पुराने फ्रांसीसी मिराज विमानों में बदलाव की अनुमति दी ताकि उन्हें रूसी आर-73 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल ढोने लायक बनाया जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि मिराज की मूल मात्रा 530-डी मिसाइल बेकार हो चुकी थीं।

यह पूरा वाकया मशहूर गीतकार शैलेंद्र के लिखे उस शानदार गीत की याद दिलाता है जो उन्होंने राजकपूर की फिल्म श्री 420 के लिए लिखा था: मेरा जूता है जापानी / ये पतलून इंगलिस्तानी / सर पे लाल टोपी रूसी / फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये पंक्तियां सन 1955 में एक नए बने देश के लिए थीं। परंतु 65 वर्ष बाद भी यह देश के सशस्त्र बलों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है।

सबसे पहले बात करते हैं बजट बनाम जीडीपी के मुद्दे का। इस वर्ष का रक्षा बजट पेंशन समेत 4.31 लाख करोड़ रुपये का है। यह राशि जीडीपी के 2 फीसदी के बराबर है। अगर पेंशन को निकाल दिया जाए तो यह राशि 3.18 लाख करोड़ रुपये यानी जीडीपी के 1.5 फीसदी के बराबर रह जाती है। यहां दो सवाल उत्पन्न होते हैं: क्या भारत इतनी कम राशि में अपना बचाव कर सकता है? और क्या भारत इससे अधिक रक्षा बजट का प्रावधान कर सकता है? तात्कालिक प्रतिक्रिया में पहले सवाल का तात्कालिक जवाब है न, लेकिन दूसरे का जवाब हां है। स्पष्टीकरण: कुछ समय पहले तक शायद मैं भी यही कहता लेकिन मैं गलत था। रणनीतिक क्षेत्र से जुड़ी बहस में जीडीपी और राष्ट्रीय बजट के बीच हमेशा अंतर नहीं किया जाता। बजट सरकार का है, जीडीपी नहीं। रक्षा व्यय पर और करीबी नजर डालने का सही तरीका है राष्ट्रीय बजट का प्रतिशत।

करीब 23 फीसदी की ऋण अदायगी के बाद 15.5 फीसदी के साथ यह बजट का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सेदार है। यह कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के समेकित 15.1 फीसदी के आंकड़े से भी ज्यादा है। जीडीपी का और आधा फीसदी या कुल बजट का 3.5 फीसदी, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों पर व्यय किया जाता है। ऐसे में कोई भी वित्त मंत्री रक्षा के लिए अतिरिक्त बजट कहां से लाएगा?

हमारे डेटा पत्रकार साथी अभिषेक मिश्रा ने सन 1986 से अब तक के रक्षा बजट के आंकड़े जुटाए। इसके मुताबिक जिस समय राजीव गांधी सैन्य विस्तार पर जोर दे रहे थे उस वक्त रक्षा बजट जीडीपी के 4 फीसदी तक पहुंचा था। यही वह दौर था जब मिराज विमानों का देश में आगमन शुरू हुआ। तब से बजट में निरंतर, स्थिर और पारंपरिक तरीके से वृद्धि हुई है और यह औसतन जीडीपी के 2.82 फीसदी के बराबर रहा (विश्व बैंक के आंकड़े)। सन 1991 के सुधार के बाद जीडीपी आंकड़ों में तेजी आनी शुरू हुई।

बीते दो दशक में करगिल की जंग के बाद बजट में औसतन सालाना 8.91 फीसदी की वृद्धि हुई। आप चीख चिल्ला सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं लेकिन अब यह स्पष्ट है कि कोई भी सरकार इतनी गैरजवाबदेह नहीं हो सकती है कि वह रक्षा व्यय में इजाफा करने के लिए नए नोट छापे या गरीबों की सब्सिडी कम करे (यह बजट का 6.6 फीसदी है) या फिर कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा या ग्रामीण विकास के बजट में कटौती करे। यह धारणा गलत और अनुचित थी कि अधिक ताकतवर मोदी सरकार कुछ नाटकीय करेगी। मोदी मूर्ख या लापरवाह सैन्यवादी नहीं हैं। मजबूत रणनीतिक रुख का यह मतलब नहीं कि वह देश को पाकिस्तान की तरह राष्ट्रीय सुरक्षा वाले मुल्क में बदल दें जो अपने खर्च के लिए आईएमएफ का मोहताज है।

देश की रणनीतिक बहस को नई हकीकत के मुताबिक ढालना होगा। हमें देखना होगा कि क्या व्यावहारिक है। अगर 2024 में जीडीपी का आकार 5 लाख करोड़ डॉलर हो जाता है तो रक्षा बजट करीब दो फीसदी रहेगा। ऐसे में बहस इस बात पर होनी चाहिए कि इस राशि से देश की किस हद तक रक्षा-सुरक्षा की जा सकेगी। मौजूदा सैन्य स्तर पर देखा जाए तो लंबी लड़ाई की स्थिति में हमारा देश पाकिस्तान से बहुत बेहतर स्थिति में है लेकिन फिलहाल लड़ाई के हालात नहीं हैं। याद रहे सन 1965 और 1971 की पिछली दो लड़ाइयां भी बमुश्किल 22 और 13 दिन चलीं। परंतु क्रिस्टीन फेयर का यह कहना भी सही है कि आज भारत अल्पकालिक लड़ाई में पाकिस्तान को नहीं हरा सकता। हमें यह सवाल उठाने की आवश्यकता है कि क्या भारत के पास यह क्षमता है कि वह पुलवामा जैसी कुटिल और असमान लड़ाइयों की स्थिति में वह पाकिस्तान को प्रतिरोधात्मक सबक सिखा सके, वह भी बिना भारतीयों की जान जोखिम में डाले। बालाकोट और उसके अगले दिन जो कुछ हुआ वह बताता है कि हमें फिलहाल ऐसी कोई बढ़त हासिल नहीं है। यह सही है कि लंबी लड़ाई में वायुसेना का कौशल निर्णायक साबित होगा लेकिन हमारे रक्षा बजट के सातवें हिस्से के बराबर रक्षा बजट और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार के बमुश्किल 3 फीसदी मुद्रा भंडार वाला देश अपनी मर्जी के चुने समय में हमें शिकस्त क्यों दे? यहां फिर वही सवाल आता है कि क्या हम अपने रक्षा बजट को सही तरीके से खर्च कर रहे हैं?

हमारी दो प्राथमिक सामरिक जरूरतें हैं: चीन के खिलाफ मजबूत बचाव जो उसे किसी तरह के भौगोलिक दुस्साहस न करने दे और पाकिस्तान बिना किसी भय की आशंका के बेमेल लड़ाइयां छेड़ने से रोकना।

दो मोर्चों पर जंग असंभव तो नहीं लेकिन इसकी संभावना कम है। भारत तीनों परमाणु हथियार संपन्न देशों के बीच अपना बचाव करने सक्षम है। कोई भी देश लंबी लड़ाई में अगर हारता है तो वह दूसरे को भी डुबाएगा। दो मोर्चों पर लड़ाई के सोच से बाहर निकलना होगा। बल्कि हमें स्पष्ट नजर आ रही हकीकत पर ध्यान देना होगा।

फिलहाल हमारी वायु सेना या थल सेना के पास पाकिस्तान के खिलाफ उक्त दंडात्मक प्रतिरोध मौजूद नहीं है। तीन सप्ताह की लड़ाई की बात तो छोड़ दें, नियंत्रण रेखा पर भी पाकिस्तान ने अब तक हमसे बेहतर हथियार, बॉडी आर्मर, स्नाइपर राइफल और गोला-बारूद तैनात कर रहा है। संप्रग के 10 वर्ष के कार्यकाल में हमने जो लापरवाही बरती और जो असंतुलन आया वह 26-27 फरवरी को उजागर हो गया। केवल हमारी नौसेना को ही आज पाकिस्तान पर निर्णायक बढ़त हासिल है। परंतु सेना का दंडात्मक इस्तेमाल शेष विश्व के लिए जरूरी जलमार्गों को असंतुलित कर सकता है। 4.31 लाख करोड़ रुपये के रक्षा व्यय में 1.12 लाख करोड़ रुपये पेंशन के मद में जाते हैं। इसके बाद तीनों सेनाओं के वेतन में 1.08 लाख करोड़ रुपये व्यय होते हैं। इसमें डीआरडीओ और असैन्य व्यय शामिल नहीं है। एक लाख करोड़ रुपये की राशि अन्य तयशुदा खर्च, रखरखाव आदि में लगते हैं। इसके बाद कुछ सौ करोड़ रुपये की राशि बचती है जो वेतन भत्तों की राशि से भी कम है। यही कारण है कि तीनों सेनाओं का आधुनिकीकरण नहीं हो पा रहा है और उन्हें जैसे-तैसे काम चलाना पड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि आखिर मायने यही रखता है कि मशीन के पीछे कौन खड़ा है, क्योंकि ...फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।

महाशक्ति बनने के आकांक्षी देश को कहीं बेहतर की जरूरत है। अगर हम ज्यादा नहीं खर्च कर सकते तो हमें समझदारीपूर्वक खर्च करना होगा। हम वेतन और पेंशन में कमी नहीं कर सकते, बल्कि हमारे जवानों को और अधिक की आवश्यकता है। परंतु क्या हमें पूर्णकालिक स्तर पर इतने अधिक सैनिक चाहिए? हमें सेना को छोटा, फुर्तीला और आक्रामक बनाने की जरूरत है। हमें अल्पकालिक सेवा और अमेरिका के क्लाइन अमेरिकन आरओटीसी (रिजर्व ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर) जैसे नए विचारों पर काम करना होगा। इस दिशा में कुछ पहल भी हो रही है क्योंकि मौजूदा सरकार संप्रग की तरह बदलाव को लेकर शंकित नहीं है। हमें सैद्धांतिक बदलाव की जरूरत है। रणनीतिकारों को भी अतीत की जंगों को भुला देना चाहिए।

कारोबारी जिंदगी के दो मुकाम: बिड़ला और ऐकोका

जिंदगीनामा

कनिका दत्ता

कारोबार जगत के दो दिग्गजों का पिछले पखवाड़े एक दिन के अंतराल में ही निधन हो गया। ली ऐकोका का 94 साल की उम्र में 2 जुलाई को निधन हुआ और अगले ही दिन बसंत कुमार बिड़ला 98 साल की उम्र में दिवंगत हो गए। एक मशहूर उद्योगपति परिवार के उत्तराधिकारी बिड़ला जहां भारतीय कारोबारी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे वहीं ऐकोका अपनी पेशेवर प्रतिभा के बल पर ग्रेट अमेरिकन ड्रीम को साकार करने में जुटे तबके के विलक्षण प्रतिनिधि थे।

बिड़ला विरासत में मिली संपत्ति के दम पर विशाल कारोबारी साम्राज्य खड़ा करने वाले भारतीय उद्यमी के प्रतीक थे। वहीं ऐकोका इटली से आकर अमेरिका में बसे माता-पिता की संतान थे और उनका बचपन काफी मुश्किलों में बीता था। पारिवारिक कारोबार के नाम पर उनके पास हॉट डॉग का एक स्टैंड भर था। फिर भी ऐकोका अमेरिका के सबसे सफल प्रबंधक बनकर उभरे। उन्होंने 'मोटाउन' की तीन में से दो बड़ी कार कंपनियों का जिस तरह से कायापलट किया था उसके बारे में आज भी प्रबंध संस्थानों में पढ़ाया जाता है।

बिड़ला परंपरागत कारोबार करने वाले परिवार से ताल्लुक रखते थे और उस परिवार का स्वतंत्रता आंदोलन से भी करीबी संबंध रहा था। उनके मशहूर पिता घनश्यामदास बिड़ला उन भारतीय उद्योगपतियों की पहली पीढ़ी का हिस्सा थे जिन्होंने कमोडिटी की खरीद-बिक्री के बजाय कंपनी संचालित कारोबार की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उस पीढ़ी के उद्यमियों ने विश्व युद्धों के समय मिले मौके का बखूबी फायदा उठाया और एजेंसी व्यवस्था को संभालने के गुर सीखे थे।

'बीके' के रूप में लोकप्रिय बिड़ला का जन्म उद्यमिता एवं धन से भरे-पूरे परिवार में हुआ था और उन्हें कम उम्र से ही कारोबारी गुर सिखाए गए थे। बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित एक लेख में कुणाल बोस ने कहा है कि बिड़ला को शेयर कारोबार में हाथ आजमाने के लिए 13 साल की उम्र में ही प्रोत्साहित किया गया था और उन्होंने पहले साल में ही 4,000 रुपये का अच्छा मुनाफा भी कमा लिया था। अपने पिता के कारोबार में प्रशिक्षु के तौर पर शामिल होने के लिए उन्होंने इच्छा न होते हुए भी प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ दिया। आजादी के समय उत्तराधिकार में मिली संपत्ति ने उन्हें अपने दम पर बड़ा साम्राज्य खड़ा करने का आधार दे दिया। उन्हें देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था स्थापित करने की नेहरू की पहल से मिले शुरुआती मौकों का भी फायदा उठाया था।

लेकिन अत्यधिक समृद्ध होते हुए भी बिड़ला पर इसका कोई असर नहीं दिखता था। गरिमापूर्ण आचरण एवं नरम स्वभाव वाले बिड़ला की कार्यशैली कलकत्ता के डलहौजी स्क्वेयर के आसपास के उद्यमियों से काफी जुदा थी। उनमें आर्थिक नीति में आसन्न अवसर पहचानने की समझ खूब थी। मसलन, सीमेंट पर नियंत्रण आंशिक रूप से हटाए जाने के बाद उन्होंने सीमेंट कारोबार खड़ा करने का मन बना लिया।

बिड़ला एक उद्यमी के तौर पर बिड़ला सीमेंट, टायर, कपड़ा एवं चाय जैसे कमोडिटी-केंद्रित कारोबार में ही लगे रहे क्योंकि उन दिनों घरेलू बाजार काफी हद तक संरक्षित थे। विदेशों में कुछ कारोबार थे लेकिन उनमें से कोई भी पूंजीवाद के गढ़ अमेरिका और यूरोप के कड़ी प्रतिस्पर्द्धा वाले बाजारों में नहीं था। भारत की अधिकांश बड़ी कंपनियों की तरह बिड़ला भी भारत में ही कारोबार करने में सहज

महसूस करते रहे और उनकी प्रबंधकीय शैली मिलनसार एवं सहृदय होते हुए भी मूलत: केंद्रीकृत एवं विवरणोन्मुख थी।

बिड़ला साम्राज्य या परिवारों के स्वामित्व वाले किसी भी भारतीय समूह में ऐकोका जैसे सख्त एवं विलक्षण प्रबंधक के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। महज मार्केटिंग रणनीति की काबिलियत ने उन्हें फोर्ड कंपनी में लंबे समय तक बचाए रखा। कंपनी के कर्ताधर्ता हेनरी फोर्ड द्वितीय अक्सर ऐकोका को यह याद दिलाते रहते थे कि मुख्यालय के बाहर उनका नाम लिखा हुआ है। आखिर में अनुचित ढंग से 1978 में ऐकोका को फोर्ड से निकाल दिया गया। उसके पहले ऐकोका ने 1964 में चार दरवाजों वाली स्पोर्ट्स कार पेश कर तहलका ही मचा दिया था। इसी तरह के उनके कुछ और प्रयोगों ने फोर्ड को डेट्रायट शहर की सबसे मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में से एक बना दिया था।

फोर्ड से निकाले जाने के दो हफ्ते बाद ही ऐकोका खस्ताहाल कंपनी क्रिसलर के प्रेसिडेंट बनाए गए थे और उन्होंने अपनी कंपनी को मुश्किल दौर से निकालने के लिए अपने पुराने बॉस रॉबर्ट मैकनामारा का डेटा-संचालित नजरिया अपनाया। अमेरिकी संसद कांग्रेस से बेलआउट पैकेज पर चर्चा, कर्मचारियों की संख्या में कटौती और नए उत्पादों की लॉन्चिंग के जरिये ऐकोका ऐसा करने में सफल रहे। क्रिसलर के बैनर तले उन्होंने मशहूर के-कार उतारी जिसे पहले फोर्ड ने नकार दिया था। 'अगर इससे बेहतर कार तलाश सकते हैं तो उसे ही खरीदें' उक्ति के साथ उतारी गई यह कार इतनी सफल रही कि क्रिसलर ने तय समय से पहले ही अपने कर्ज उतार दिए।

व्यक्तिगत स्तर पर बिड़ला पारिवारिक मूल्यों को काफी अहमियत देते थे। उन्होंने एक बार कहा था, 'धन के लिए सम्मान उसे खड़ा करने में लगी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से पैदा होता है।' बिड़ला के उलट तीन बार शादी करने वाले ऐकोका खुद को आगे बढ़ाने में थोड़ा भी संकोच नहीं करते थे और 1980 के दशक में वह क्रिसलर के कई विज्ञापनों में भी नजर आए थे। उन्होंने 1984 में प्रकाशित अपनी रोचक आत्मकथा में कहा था, 'मैं खुद को भला दिखाने में नहीं बल्कि पैसे कमाने में रुचि रखता था।'

इन दोनों कारोबारी दिग्गजों की विरोधाभासी जिंदगियां बीसवीं सदी का हिस्सा होते हुए भी इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक के मुहाने पर भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। उनके जीवन की कहानियां दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में मौजूद अवसरों की समानता के बारे में बहुत कुछ कहती हैं।

कानाफूसी

मतभेद समाप्त करने की कोशिश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के एक अन्य शीर्ष नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले दिनों अपने मतभेद दरकिनार करते हुए बंद कमरे में इस बात पर विचार विमर्श किया कि आखिर कैसे प्रदेश की कांग्रेस सरकार को भारतीय जनता पार्टी के आसन्न हमलों से सुरक्षित रखा जाए। इससे कुछ दिन पहले कैबिनेट की एक बैठक में सिंधिया और कमलनाथ के समर्थक मंत्री खुलकर आमने-सामने आ गए थे। इस बैठक में दोनों नेताओं ने करीब 25 मिनट तक चर्चा की। यह बैठक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट द्वारा आयोजित रात्रि भोज के दौरान हुई। सिलावट को सिंधिया का समर्थक माना जाता है। इस रात्रिभोज में 90 विधायक और 27 मंत्री शामिल हुए लेकिन विंध्य के कद्दावर नेता अजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मंत्री पीसी शर्मा की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। दिलचस्प बात यह है कि सिंधिया ने भी प्रदेश के विधायकों से वही बात कही जो प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों से कही थी-अनावश्यक वक्तव्य जारी न करें, मीडिया से ज्यादा बातचीत न करें।

आपका पक्ष

हर किलोमीटर पर हो जल संचयन

आने वाले दशक में विश्व में जलसंकट काफी गहराने की आशंका दिख रही है। विश्व के कई देशों में अभी से ही जल संरक्षण बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। कई देशों में भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया है जहां से पानी निकालना संभव नहीं है। दक्षिण भारत में चेन्नई में घोर जलसंकट छा गया है। वहां दूसरे शहरों से ट्रेन से पानी मंगवाया जा रहा है। पिछले दिनों सैटेलाइट से ली गई एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें एक वर्ष में चेन्नई की झील में पानी की कमी के अंतर को दिखाया गया था। इधर, मॉनसून के एक माह बीत जाने के बाद भी राजधानी दिल्ली तथा इससे सटे नोएडा में बारिश नहीं हो रही है। जबकि दिल्ली-नोएडा से सटी अन्य जगहों में जोरदार बारिश हुई है। देश की राजधानी में भी जल संकट छाया हुआ है। कई कॉलोनियों में पानी की आपूर्ति टैंकरों से की जा रही है। दिल्ली में यमुना नदी तो है लेकिन यह लगभग एक नाले में तब्दील हो चुकी है। यमुना नदी इतनी प्रदूषित हो चुकी है जिसका पानी उपयोग करने लायक नहीं बचा है। दिल्ली में हरियाणा से नहर के जरिये पानी मंगाया जाता है। वह भी दो राज्यों के बीच कई साल पहले हुए करार के तहत हरियाणा निर्धारित पानी ही नहर में छोड़ता है जो दिल्ली के लिए अब नाकाफी है। बहरहाल जलसंकट की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार बारिश का पानी संचयन करने की योजना बनाई है। इसके लिए यमुना नदी के दोनों किनारों पर तालाब खुदवाए जाएंगे या वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) देश भर सरकारी कॉलोनियों में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए जल संचयन के ढांचे निर्मित करेगा। यह एक अच्छी पहल है। देश की सभी राज्य सरकारों को हर एक किलोमीटर में वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए जिससे बारिश के दिनों में पानी जमा किया जा सके।

अदिति कुमारी, नई दिल्ली

सरकार को बारिश का पानी संचयन करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए

सोशल मीडिया पर निगरानी

इस समाचार पत्र में 12 जुलाई के अंक में प्रकाशित लेख 'सोशल मीडिया पर निगरानी' पढ़ा। लेख के अनुसार मानव संसाधन मंत्रालय का यह प्रयास है कि करीब 900 उच्च शिक्षण संस्थान सकारात्मक सोशल मीडिया प्रोफाइल तैयार करे। इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे करीब तीन करोड़ छात्रों से यह कहा जाएगा कि वे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल संस्थान के प्रोफाइल से जोड़ें। इससे छात्र व्यापक निगरानी ढांचे के शिकार हो सकते हैं जिससे उनकी निजता भंग होने की आशंका रहेगी। बहरहाल आम जनजीवन में देखें तो सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी हो रही होती है। किसी संस्थान में पढ़ने वाला छात्र अगर संस्थान की खामियां उजागर करता है तो उसे संस्थान की ओर से लताड़ लगाई जाती है। वहीं निजी क्षेत्र की कंपनियों की बात करें तो मानव संसाधन विभाग अपने कर्मियों के प्रोफाइल पर पूरी नजर रखता है। अगर कोई कर्मी कंपनी की बुराई करता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। सोशल मीडिया आधुनिक युग का एक हथियार है जिसे काफी सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके उचित इस्तेमाल के लिए कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए।

अजय कुमार, गुड़गांव

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।